www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 05 | अंक – 40 | जौनपुर, शुक्रवार, 25 सितम्बर 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रुपये

संक्षिप्त खबरें

मोदी का वादा याद दिलाकर जम्मू–कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पेश – उमर अब्दुल्ला

कश्मीर, (एजेंसी)। जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में राज्य का दर्जा बहाल करने का औपचारिक प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को उसके उन पुराने वादों की याद दिलाई, जिनमें परिसीमन और चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जम्मू–कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने का आश्वासन दिया गया था। विधानसभा के पटल पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न मंचों से जम्मू–कश्मीर की जनता को तीन चरणों वाली प्रक्रिया की प्रतिबद्धता जताई गई थी। विधानसभा में बोलते हुए, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू–कश्मीर के लोगों से तीन चरणों वाली प्रक्रिया का वादा किया गया था – परिसीमन, चुनाव और फिर राज्य का दर्जा बहाल करना – और उन्होंने तर्क दिया कि पहले दो चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं। प्रस्ताव पेश करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, संसद, सुप्रीम कोर्ट और अन्य मंचों पर हमसे तीन चरणों – परिसीमन, चुनाव और राज्य का दर्जा – के बारे में वादा किया गया था।ष उन्होंने कहा कि लोगों ने बड़ी संख्या में चुनावों में हिस्सा लिया और अब तीसरा चरण – राज्य का दर्जा बहाल करना – बाकी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, ष्भारी मतदान हुआ। लोगों को मजबूर नहीं किया गया, लोगों ने तीसरे चरण के लिए वोट दिया।

भाजपा नेता नितिन नवीन ने जयपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत दिलाई शपथ

जयपुर, (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शुक्रवार सुबह यहां अल्बर्ट हॉल पर विकसित भारत जन सेवा अभियान के तहत आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। नवीन ने शपथ दिलाते हुए कहा, ''हम हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह दो घंटे स्वच्छता के लिए समर्पित करेंगे। हम स्वच्छता को लेकर सजग और जागरूक रहेंगे।'' बाद में उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा,'' अब 'स्वच्छता ही सेवा' का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशव्यापी जनभागीदारी का स्वरूप ले चुका है। इसी सेवा भावना को आगे बढ़ाते हुए आज जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल परिसर में 'सेवा संकल्प अभियान' के निमित्त स्वच्छता प्रहरियों के साथ स्वच्छता की शपथ ली, उनसे मिलकर हालचाल जाना तथा उन्हें सम्मानित किया।'' इस दौरान वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे। नवीन व शर्मा ने स्वच्छता मित्रों को अंगवस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया और बातचीत करके उनके हालचाल जाने।

यूपी के 3.54 लाख रसोइयों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, अक्टूबर से खातों में पहुंचेगा बढ़ा हुआ मानदेय

लखनऊ, (संवाददाता)। पीएम पोषण योजना के तहत विद्यालयों में बच्चों का भोजन बनाने वाले करीब 3.54 लाख रसोइयों को अक्टूबर में बढ़ा हुआ मानदेय समय पर मिलेगा। प्रदेश सरकार ने सितंबर से रसोइयों का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह किया है। जिलों में मानदेय का भुगतान जिलाधिकारी के माध्यम से होता है। हर माह भुगतान में देरी की शिकायतों को देखते हुए शासन ने सभी जिलों को समय से मानदेय जारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के करीब 1.42 लाख राजकीय, परिषदीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में पीएम पोषण योजना संचालित है। वर्तमान में 1.46 करोड़ छात्र– छात्राएं पीएम पोषण से जुड़े हैं। योजना के तहत प्राथमिक कक्षाओं के प्रत्येक बच्चे के भोजन में 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन का मानक निर्धारित है। बच्चों को हर सोमवार मौसमी फल भी दिए जा रहे हैं। भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से 7849 विद्यालयों में 9,91,338 विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा सात जिलों में अक्षय पात्र संस्था के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए भोजन तैयार कर उपलब्ध कराया जा रहा है।प्रदेश के आठवीं कक्षा तक के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में करीब 1.47 करोड़ बच्चों को मिड–डे मील दिया जाता है. इन बच्चों के लिए खाना तैयार करने का काम करीब 3,53,536 रसोइये करते हैं. अभी रसोइयों को हर महीने 2,000 रुपये मिलते हैं. इसमें 600 रुपये केंद्र सरकार और 1,400 रुपये राज्य सरकार देती है. अब राज्य सरकार अपनी तरफ से 1,000 रुपये और देगी. इसके बाद रसोइयों को हर महीने कुल 3,000 रुपये मिलेंगे. रसोइयों को साल में मिलने वाला 500 रुपये का यूनिफॉर्म भत्ता पहले की तरह मिलता रहेगा।

पीएम मोदी ने बताया कैसे भारत बना मैन्युफैक्चरिंग का नया ग्लोबल प्लेयर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 'मेक इन इंडिया' अभियान के 12 वर्ष पूरे होने पर देश की औद्योगिक शक्ति में आए बदलाव का जिक्र किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, "भारत में ज्यादा उत्पादन, भारत में ज्यादा निवेश, भारत से ज्यादा निर्यात। हर सेक्टर में बदलाव साफ दिख रहा है!" 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई इस पहल का लक्ष्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और इनोवेशन का वैश्विक हब बनाना था। आज यह योजना 27 क्षेत्रों में सक्रिय है, जिनमें 15 मैन्युफैक्चरिंग और 12 सर्विस सेक्टर शामिल हैं। मेक इन इंडिया आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन लगभग सात गुना बढ़ गया है। 2014–15 में यह 1.9 लाख करोड़ रुपये था, जो 2025–26 में बढ़कर 13.11 लाख करोड़ रुपये हो गया। मोबाइल फोन उत्पादन तो करीब 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपये से 6.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

वॉल्यूम के हिसाब से भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है। देश में बने रक्षा उत्पादों की वैल्यू 2014–15 में 46,429 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2025–26 में यह आंकड़ा बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये हो गया है। सरकारी फैक्टशीट के मुताबिक 2024–25 में गाड़ियों का उत्पादन 31.03 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया, जो 2014–15 की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है। 2020–21 के मुकाबले भी विभिन्न श्रेणियों की गाड़ियों के उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई।

भारत–जापान ने वन प्रबंधन क्षमता मजबूत करने के लिए शुरू किया प्रोजेक्ट

नई दिल्ली, (एजेंसी)।केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के सहयोग से मंत्रालय की ओर से आयोजित 'प्रभावी वन प्रबंधन के लिए क्षमता वृद्धि' प्रोजेक्ट की लॉन्च वर्कशॉप का उद्घाटन किया। वर्ष 2025–26 से 2031–32 तक चलने वाले इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य वन और वन्यजीव प्रबंधन की बदलती जरूरतों, जलवायु संबंधी चुनौतियों और

पर्यावरण से जुड़ी नई चिंताओं से निपटने के लिए फ्रंटलाइन वन कर्मियों की क्षमता बढ़ाना है। वर्कशॉप को संबोधित करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु कार्रवाई, जैव विविधता संरक्षण और वनों पर निर्भर समुदायों की आजीविका के लिए जंगलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने वन कर्मियों की तकनीकी और फील्ड स्तर की क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। इसमें खास तौर पर जंगल की आग के प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु कार्रवाई जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। मंत्री ने क्षेत्र–विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इन मॉड्यूल में पारंपरिक ज्ञान, वैज्ञानिक तरीकों और आधुनिक तकनीकों का समन्वय होना चाहिए। उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पायलट प्रोजेक्ट और वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करने को भी इस पहल के महत्वपूर्ण हिस्सों में शामिल किया।

उत्तर प्रदेश का ब्रह्मोस उड़ा रहा पाकिस्तान की नींद, ग्रेटर नोएडा से शाह की हुंकार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कहा कि राज्य में बन रही ब्रह्मोस मिसाइलों की वजह से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। उन्होंने राज्य की बढ़ती डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं और निवेश के माहौल पर जोर दिया। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में चौथे एडिशन के उद्घाटन के मौके पर शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी छह नोड्स झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और कानपुर में निवेश आ रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस फैसिलिटी का जिक्र करते हुए शाह ने कहा आज यूपी में बनी ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तान की नींद उड़ा रही हैंय यह हो रहे बदलाव का एक बड़ा संकेत है। उन्होंने राज्य में डिफेंस प्रोडक्शन के विस्तार के उदाहरण के तौर पर अमेठी में बनी सीएके–203 असॉल्ट राइफलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा इसी तरह, अमेठी में बनी असॉल्ट राइफलें नक्सलियों और आतंकवादियों, दोनों की नींद उड़ा रही हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन मई 2025 में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हिस्से के तौर पर किया गया था। यह फैसिलिटी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का काम करती है। यहाँ बनी ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को अक्टूबर 2025 में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। यह फैसिलिटी लगभग 200 एकड़ जमीन पर करीब 300 करोड़ के निवेश से बनाई गई थी। इसका मकसद देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना और सहायक उद्योगों व कुशल रोजगार का इकोसिस्टम तैयार करना था। शाह ने कहा कि ग्लोबल उथल–पुथल के बावजूद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। उन्होंने एक्सपोर्ट के मौके बढ़ाने का श्रेय मोदी सरकार की आर्थिक और व्यापार नीतियों को दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की सोच पूर्वाग्रह से भरी है, वे भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाते।

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू, 351 बसें रवाना

मध्य प्रदेश, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में 21 साल बाद एक बार फिर सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। प्रदेशवासियों को सुगम, सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण–अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25 सितंबर को मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की गई। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रिमोट के जरिए सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान 351 बसों को रवाना किया गया। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के जरिए प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बस कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। योजना के तहत प्रदेश की 75: ग्राम पंचायतों तक परिवहन सेवा का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन के लिए बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत वर्ष 2031 तक प्रदेश में 15 हजार बसें संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पहले वर्ष में 1,500 बसों के संचालन की योजना है। इसके बाद हर साल लगभग 2,500 से 3,000 बसें बेड़े में शामिल की जाएंगी। योजना के तहत पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए बसों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए बसों के संचालन, लोकेशन और समयबद्धता की रियल–टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे बसों के परिचालन पर नजर रखने और सेवा को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। मध्यप्रदेश यात्री परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसकी सात सहायक कंपनियों में कमांड–कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं।

राधाकृष्णन का ग्लोबल साउथ से आह्वान – सुरक्षा और विकास चुनौतियों पर साथ मिलकर लड़ें

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को ग्लोबल साउथ के देशों से तेजी से बदलती सुरक्षा और विकास संबंधी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए निरंतर संवाद, आपसी सीख और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने का जोरदार आह्वान किया। उन्होंने साफ कहा कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी देश अकेले रहकर उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर सकता। इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट प्रोग्राम (इन–स्टेप) के चौथे संस्करण के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने वर्तमान रणनीतिक माहौल की जटिलताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पारंपरिक सुरक्षा चिंताओं के साथ अब प्रौद्योगिकी, साइबरस्पेस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक

मजबूती, समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आपूर्ति शृंखला जैसे मुद्दे भी गहराई से जुड़े हुए हैं।" "सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि इन–स्टेप कार्यक्रम वैश्विक घटनाक्रमों के दीर्घकालिक प्रभावों को समझने, व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण विकसित करने और सही प्रतिक्रियाएं तैयार करने का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कार्यक्रम की मूल भावना को तीन शब्दों में समेटाकृ "वैश्विक स्तर पर सोचें, रणनीतिक रूप से जुड़ें और सामंजस्य के साथ काम करें।" उन्होंने अंतरराष्ट्रीय विमर्श को आकार देने में ग्लोबल साउथ की अहम भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि इन देशों के विविध अनुभव और विकास प्राथमिकताएं लचीलापन, विकास, सुरक्षा, सुशासन और सहयोग के क्षेत्र में बहुमूल्य सीख देती हैं।

नोएडा में शुरू होगा चार दिवसीय आयुष महोत्सव, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा का दिखेगा संगम

ब्यूरो चेफ सत्य प्रकाश उपाध्याय

नोएडा के सेक्टर–62 स्थित एक्सपो मार्ट में 25 सितंबर से चार दिवसीय आयुष महोत्सव 2026 का आयोजन होने जा रहा है। महोत्सव के माध्यम से आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा सहित विभिन्न पारंपरिक चिकित्सा

पद्धतियों और आयुष उत्पादों को एक बड़े मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन को लेकर नोएडा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयुष क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने महोत्सव की तैयारियों, उत्पादों और चिकित्सा पद्धतियों की उपलब्धता की जानकारी साझा की। आयोजकों के अनुसार, महोत्सव का उद्देश्य भारतीय चिकित्सा परंपराओं और आयुर्वेद के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना तथा आधुनिक समय में इनके महत्व को सामने लाना है। चार दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में विशेषज्ञों, संस्थानों और आयुष क्षेत्र से जुड़े विभिन्न प्रतिष्ठानों की भागीदारी रहेगी। आयोजकों को उम्मीद है कि यह महोत्सव नोएडा से आयुष क्षेत्र को देशभर में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

बारिश में भी नहीं बदला अयोध्या आने का संकल्प, रामलला के दर्शन कर भावविभोर हुई भजन गायिका व प्रसिद्ध कलाकार स्वीटी गुप्ता

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या की पहचान देश मे ही नहीं,बल्कि विदेशों में भी बन चुकी है।रामलला के दर्शन के लिए देश–विदेश से श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या इसका प्रमाण है।यह बातें प्रसिद्ध भजन गायिका व प्रसिद्ध कलाकार स्वीटी गुप्ता ने शुक्रवार को अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन–पूजन के बाद कहीं।शहर के एक होटल में बातचीत के दौरान स्वीटी गुप्ता ने बताया कि खराब मौसम के बावजूद उन्होंने अयोध्या आने का अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं बदला।वे सुबह हवाई मार्ग से अयोध्या पहुंचीं।सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन–पूजन किया,इसके बाद रामलला के दरबार में पहुंचकर प्रभु श्रीराम के चरणों में शीश नवाया।मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि बारिश के बीच रामलला का दर्शन करना उनके लिए बेहद भावुक और जीवन को धन्य करने वाला क्षण रहा।उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या की पहचान पूरी दुनिया में बनी है। आज यहां वायु, रेल और सड़क मार्ग से देश के विभिन्न हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध है। उन्होंने इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की।उन्होंने बताया कि भजन गायिका स्वीटी गुप्ता ने बताया कि वे पिछले 18 वर्षों से रामलीला से जुड़ी हुई हैं।वर्ष 2020 से उन्होंने अयोध्या की रामलीला में भाग लेना शुरू किया और लगातार माता सीता की भूमिका निभाकर उनके चरित्र को जीवंत करती आ रही हैं।उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में होने वाली रामलीला में माता सीता की भूमिका में नजर आएंगी।उन्होंने बताया कि इसके अलावा वे दिल्ली की लव–कुश रामलीला लाल किला,श्री धार्मिक रामलीला लाल किला,दिल्ली कैंट सहित कई अन्य रामलीलाओं में भी माता सीता का किरदार निभा चुकी हैं।रामलला के दर्शन के बाद स्वीटी गुप्ता ने कनक भवन में भी दर्शन–पूजन किया और इसके बाद महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गईं।

संपादकीय

कंपनियों के लिए नई चुनौती

रूटो की आम छवि अमेरिका समर्थक की है, लेकिन हाल में उन्होंने चीन से संबंध मजबूत किए हैं। चीन का पहलू अफ्रीका में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए नई चुनौती बन कर उभरा है। बढ़ते राजनीतिक विरोध की चुनौती झेल रहे केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो का भारतीय कंपनी– टाटा केमिकल्स मगाडी को देश से निकालने का फैसला विवादास्पद है। समझा जाता है कि केन्या में विदेशी निवेशकों के प्रति फैल रही भावना को शांत करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। बहरहाल, यह निर्णय टाटा ग्रुप की अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए तगड़ा झटका है। इससे विदेशों में निवेश कर रही हर भारतीय कंपनी को उचित सबक लेना चाहिए। केन्या के स्थानीय समुदायों में टाटा कंपनी के खिलाफ लंबे समय से असंतोष पनप रहा था। शिकायत थी कि लेक मगाडी के समृद्ध सोडा ऐश संसाधनों का इस्तेमाल तो खूब हुआ, लेकिन बुनियादी ढांचे या रोजगार के रूप में उस क्षेत्र को कोई लाभ नहीं हुआ। अब रूटो ने वादा किया है कि वे वहां ऐसी विदेशी कंपनी को ठेका देंगे, तो स्थानीय विकास के लिए भी निवेश करे। चर्चा है कि ये ठेके चीनी कंपनियों को दिए जाएंगे। रूटो की आम छवि अमेरिका समर्थक नेता की है, लेकिन हाल में उन्होंने चीन से संबंध मजबूत किए हैं। चीन का पहलू अफ्रीका में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए नई चुनौती बन कर उभरा है। जिस ढंग से टाटा कंपनी को निकालने का फैसला हुआ, वैसे कदमों से सामान्यतरू सभी विदेशी निवेशकों में नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। लेकिन चीनी कंपनियां अक्सर जोखिम उठाते हुए ऐसे हालात का लाभ उठाने की कोशिश करती हैं। साथ ही इस घटना ने उजागर किया है कि अफ्रीका में आई नई जन चेतना के बीच वहां कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए केवल कानून का पालन ही काफी नहीं रह गया है। बल्कि अब चुनौती स्थानीय समुदायों को संतुष्ट रखते हुए अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की है। इस सिलसिले में पर्यावरण संरक्षण एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन कर उभरा है। गुजरे डेढ़ दशक में अडानी ग्रुप, रिलायंस, जीएमआर, जिंदल, एस्सार आदि जैसी भारतीय कंपनियों को या तो कुछ देशों से निकाला गया है, या वहां उनके साथ हुए करार बाद में रद्द कर दिए गए। ऐसी घटनाओं से देश की छवि बिगड़ती है। भारतीय कंपनियों को इस बात ख्याल रखना चाहिए।

सेहतमंद भविष्य के लिए आयुर्वेद

प्रतापराव जाधव

दुनिया अब सेहतमंद होने के मायने पर नए सिरे से सोच रही है। आज स्वास्थ्य–देखभाल का मतलब सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं हैय बल्कि इसका मकसद बीमारियों को रोकना, तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना और ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करना है, जो बदलती जीवनशैली, पर्यावरण के दबाव और नई स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर सके। इस बदलते परिदृश्य में, आयुर्वेद भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टि की पेशकश करता है। 11वें आयुर्वेद दिवस की थीम, ष्सेहतमंद भविष्य के लिए आयुर्वेदष् और ष्एक स्वास्थ्य, एक भविष्यष् का विजन इस विचार को बहुत खूबसूरती से पेश करता है। यह हमें याद दिलाता है कि मानव स्वास्थ्य का कोई अलग–थलग अस्तित्व नहीं होता। लोगों, समुदायों, पशुओं और पर्यावरण का स्वास्थ्य आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। आयुर्वेद ने हमेशा बीमारी से बचाव, संतुलित जीवन, सही खान–पान, दैनिक दिनचर्या और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने पर बहुत जोर दिया है। ऐसे समय में जब जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ, उपापचय विकार, तनाव और दूसरी गैर–संक्रामक बीमारियाँ समाज पर बोझ बढ़ा रही हैं, ये सिद्धांत और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। लेकिन आयुर्वेद को आगे ले जाने का मतलब सिर्फ पीछे मुड़कर देखना नहीं हो सकता। इसके भविष्य को शोध, साक्ष्यों, नवाचार और गुणवता के जरिए आकार दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि आयुर्वेद से जुड़े ज्ञान का अध्ययन आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से हो और उसे ऐसे समाधानों में बदला जाए, जो आज की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करते हों। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत ने इस यात्रा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापनाय आयुर्वेद और अन्य आयुष प्रणालियों को एक मजबूत संस्थागत आधार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ा है। तब से, इसका दायरा संरक्षण और प्रचार–प्रसार से बढ़कर शोध, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, गुणवत्ता आश्वासन, नवाचार और वैश्विक सहयोग तक विस्तृत हो गया है। स्वास्थ्य देखभाल को असल में मरीज की जरूरतों पर केंद्रित होना चाहिए। जहां उपचार उपयुक्त और साक्ष्य समर्थित हो, वहाँ विभिन्न स्वास्थ्य प्रणालियाँ एक–दूसरे की पूरक बन सकती हैं और स्वास्थ्य के प्रति व्यापक दृष्टिकोण में योगदान दे सकती हैं। जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में आयुष सेवाओं का एकीकरण और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विस्तार, रोकथाम और समग्र स्वास्थ्य सेवा को ज़्यादा सुलभ बनाने के हमारे संकल्प को प्रतिबिंबित करते हैं। भारत आयुर्वेद को दुनिया तक भी पहुँचा रहा है। आयुर्वेद दिवस के पिछले आयोजनों ने दिखाया है कि स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति भारत के नजरिए को दुनिया भर में कैसा समर्थन मिल सकता है। आयुर्वेद दिवस ने भारत की स्वास्थ्य परंपराओं के लिए एक वैश्विक अवसर का निर्माण किया है और आयुर्वेद तेजी से कल्याण, रोकथाम और सतत स्वास्थ्य सेवा पर होने वाली अंतरराष्ट्रीय बातचीत का हिस्सा बन रहा है। इस बढ़ती वैश्विक रुचि के साथ एक उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आती है। आयुर्वेद को विश्वसनीय शोध, नैदानिक सबूतों, मजबूत गुणवत्ता मानकों और जिम्मेदार संचार का समर्थन मिलना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, आयुष शैक्षिक विभाग, नैदानिक शोध और विनियामक तालमेल की दिशा में किए जा रहे प्रयास भारत से बाहर आयुर्वेद के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इसकी वैश्विक पहुँच का विस्तार करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि इस विकास के साथ भरोसा और वैज्ञानिक विश्वसनीयता भी जुड़ी हो। ष्एक स्वास्थ्य, एक भविष्यष् का विजन हमें अस्पतालों और दवाओं से आगे ले जाता है। एक स्वस्थ भविष्य हमारे पर्यावरण, हमारे खान–पान और उन प्राकृतिक संसाधनों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, जिन पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए, औषधीय पौधे स्वास्थ्य सेवा को कृषि, आजीविका और जैव विविधता से जोड़ते हैं। उनकी स्थायी खेती से किसानों के लिए आर्थिक अवसर पैदा हो सकते हैं और साथ ही कीमती प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी योगदान मिल सकता है। प्रौद्योगिकी भी एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती है। आज भारत के पास अपने व्यापक आयुर्वेदिक ज्ञान को आधुनिक शोध क्षमताओं, डिजिटल तकनीक, डेटा विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उभरते उपायों के साथ जोड़ने का मौका है। यह संयोजन शोधकर्ताओं को पारंपरिक तरीकों का ज़्यादा सटीकता से अध्ययन करने और नवाचार के नए अवसरों को सामने लाने में मदद कर सकता है। फिर भी, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव लोगों के जीवन में आना चाहिए। आयुर्वेद दिवस को केवल साल में एक बार मनाया जाने वाला आयोजन बनकर नहीं रहना चाहिए। इसे हमारे घरों, स्कूलों, कार्यस्थलों और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली आधारित एक व्यापक अभियान को बढ़ावा देना चाहिए।

आईआईटी बॉम्बे के छात्र आत्महत्या से जुड़े सवाल

ललित

आईआईटी बॉम्बे के द्वितीय वर्ष के बीटेक छात्र साहिल वाकोडे की 18 सितंबर 2026 को हुई मृत्यु ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की कार्यप्रणाली, विद्यार्थियों पर बढ़ते शैक्षणिक दबाव, परीक्षा में बढ़ती अनैतिकता, शिक्षकों की जवाबदेही, मानसिक स्वास्थ्य और परिसरों में राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे अनेक गंभीर प्रश्न एक साथ खड़े कर दिए हैं। इस घटना को फिलहाल आत्महत्या के रूप में रिपोर्ट किया गया है, इसके पीछे की परिस्थितियों और किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी का निर्धारण जांच का विषय है। मुंबई पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है। इसलिए किसी व्यक्ति को घटना के लिए दोषी ठहराना जांच पूरी होने से पहले उचित नहीं होगा। घटना से पहले परीक्षा के दौरान साहिल के मोबाइल और कथित रूप से एआई चौटजीपीटी के इस्तेमाल को लेकर संस्थागत कार्रवाई की स्थिति बनी थी। इसके बाद छात्रों में यह धारणा पैदा हुई कि मामले को जिस तरीके से संभाला गया, उसमें पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं थी। संस्थान ने बाद में अपने पूर्व सार्वजनिक बयान के लिए माफी मांगते हुए स्वीकार किया कि जांच पूरी होने से पहले घटना से जुड़े विवरण सार्वजनिक करना उचित नहीं था। संबंधित प्रोफेसर को डीन के प्रशासनिक पद से हटाया गया है, जबकि उनके विरुद्ध दर्ज मामले में अंतिम निष्कर्ष अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। इस घटना के बाद तीन दिनों तक छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ और 18 सूत्रीय मांगपत्र सामने आया। इन मांगों में स्वतंत्र जांच, शिक्षकों के विरुद्ध शिकायतों की स्पष्ट प्रक्रिया, छात्र–प्रतिनिधित्व, बेहतर काउंसलिंग, चौबीसों घंटे मनोचिकित्सकीय सहायता, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण और परीक्षा में अनियमितता के मामलों को संभालने के लिए अधिक मानवीय प्रक्रिया जैसी बातें शामिल हैं। आईआईटी बॉम्बे के निदेशक ने छात्रों के साथ बातचीत के बाद इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए, हालांकि संस्थान की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि आगे की कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी। यहीं से इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है। क्या शिक्षा संस्थान में अनुशासन और मानवीय संवेदना एक–दूसरे के विरोधी हैं? निश्चित रूप से नहीं। परीक्षा में नकल, मोबाइल का अनुचित इस्तेमाल अथवा एआई के माध्यम से अनुचित सहायता लेना शिक्षा की विश्वसनीयता के लिए गंभीर चुनौती है। यदि उच्च शिक्षण संस्थान ऐसी अनैतिकताओं को रोकने में असफल होते हैं तो डिग्री, शोध और प्रतिभा की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। लेकिन दूसरी ओर अनुशासनात्मक कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिसमें आरोप की निष्पक्ष जांच, छात्र को अपनी बात रखने का अवसर, अपील की व्यवस्था और मानसिक स्थिति को समझने की संवेदनशीलता शामिल हो। अपराध या अकादमिक कदाचार को नजरअंदाज करना भी गलत है और किसी छात्र को बिना समुचित प्रक्रिया के सामाजिक रूप से दोषी ठहरा देना भी। आज एआई ने शिक्षा के सामने एक बिल्कुल नई चुनौती खड़ी कर दी है। चौटजीपीटी जैसे उपकरण ज्ञान प्राप्त करने, शोध करने और सीखने में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा में अनुचित तरीके से इनका इस्तेमाल शैक्षणिक ईमानदारी का प्रश्न बन जाता है। इसलिए केवल प्रतिबंध पर्याप्त नहीं होंगे। विश्वविद्यालयों को यह स्पष्ट करना होगा कि एआई का उपयोग कहां स्वीकार्य है, कहां निषिद्ध है और उल्लंघन की स्थिति में कौन–सी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। शिक्षकों को भी केवल दंड देने वाले अधिकारी की भूमिका से आगे बढ़कर मार्गदर्शक की भूमिका निभानी होगी। साहिल प्रकरण ने जातिगत भेदभाव के आरोपों को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है। परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है, जबकि संस्थान की ओर से यह कहा गया कि छात्र ने पहले एससीध्एसटी सेल या प्रशासन के समक्ष ऐसी शिकायत नहीं की थी। इन दोनों पक्षों में से सत्य क्या है, इसका निर्णय जांच के बाद ही हो सकता है। लेकिन इससे एक व्यापक तथ्य सामने आता है–किसी भी विद्यार्थी को अपनी जाति, आर्थिक स्थिति, भाषा, क्षेत्र या सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण स्वयं को अकेला या असुरक्षित महसूस नहीं होना चाहिए। भारत में उच्च शिक्षा को लेकर नियामकीय ढांचा भी लगातार अधिक जवाबदेही और छात्र–केंद्रित व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। यूजीसी की 2023 की छात्र शिकायत निवारण संबंधी नियमावली के साथ–साथ 2026 में प्रमोशन आफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन भी सूचीबद्ध हैं। इसका मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि विद्यार्थी के अधिकार सुरक्षित रहें, शिकायतों का स्वतंत्र और समयबद्ध निवारण हो तथा संस्थान अपनी जिम्मेदारी से बच न सकें। लेकिन यहां एक सावधानी भी आवश्यक है। कानून का अर्थ यह नहीं हो सकता कि हर दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद बिना जांच किसी शिक्षक या अधिकारी को अपराधी घोषित कर दिया जाए। शिक्षक निश्चित रूप से कानून से ऊपर नहीं हैं, लेकिन वे कानून की प्रक्रिया से नीचे भी नहीं हैं। यदि किसी शिक्षक ने भेदभाव, उत्पीड़न, धमकी या अन्य गैरकानूनी आचरण किया है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यदि उसने संस्थागत नियमों के तहत अकादमिक कदाचार पर कार्रवाई की है, तो उस कार्रवाई की वैधानिकता और अनुपातिकता की जांच भी उतनी ही जरूरी है। यही न्यायपूर्ण व्यवस्था का आधार है। सबसे चिंताजनक पहलू तब सामने आता है जब किसी दुखद घटना के बाद विश्वविद्यालय का परिसर राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बनने लगता है। राजनीतिक दलों और बाहरी संगठनों को छात्रों की आवाज उठाने का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन शिक्षा

परिसर की मूल प्रकृति बची रहनी चाहिए। यदि हर प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक नारों, धरनों और दबाव की राजनीति से तय होने लगे तो विश्वविद्यालय में अकादमिक स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर यदि प्रशासन छात्रों की आवाज को केवल आंदोलन या राजनीति कहकर खारिज कर दे तो संस्थागत विश्वास और कमजोर होगा। रास्ता दोनों के बीच है–संवाद, पारदर्शिता और स्वतंत्र जांच। आईआईटी जैसे संस्थानों से देश केवल इंजीनियर, वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी तैयार करने की अपेक्षा करता है। इसलिए सफलता का पैमाना केवल प्लेसमेंट, रैंकिंग, पेटेंट और वैश्विक प्रतिष्ठा नहीं हो सकता। यह भी देखना होगा कि वहां विद्यार्थी अपने प्रश्न कितनी सहजता से उठा सकता है, शिक्षक से असहमति कितनी सुरक्षित है, शिकायत का समाधान कितनी जल्दी होता है और संकट की घड़ी में संस्थान छात्र के साथ किस तरह खड़ा होता है। साहिल की मृत्यु को किसी एक प्रोफेसर, किसी एक प्रशासनिक निर्णय या किसी एक राजनीतिक संगठन तक सीमित कर देना इस त्रासदी के व्यापक संदेश को छोटा कर देगा। असली प्रश्न यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था प्रतिभा के साथ संवेदना, अनुशासन के साथ संवाद और अधिकार के साथ जवाबदेही का संतुलन कैसे बनाए? छात्रों को ईमानदार होना सीखना होगा,।

अगर अमेरिका ने सौ प्रतिशत का टैरिफ थोपा तो

उमेश

अमेरिकी संसद के दोनों सदनों से 'सैंक्शनिंग रशा एंड ईरान एक्ट' के पारित होने को लेकर देश में आशंकाओं के बादलों का उठना स्वाभाविक है। आज जिस आर्थिकी और विश्व व्यवस्था को तकरीबन पूरी दुनिया ने अपना रखा है, उसकी वजह से पूरी दुनिया को लगता है कि अमेरिका के सहयोग के बिना वह एक कदम आगे नहीं रख सकती। वैश्विक आर्थिकी में डालर के वर्चस्व के चलते ज्यादातर देशों को लगता है कि अगर अमेरिका की आंखें टेढ़ी हुईं तो उस पर महाविपत्ति आ जाएगी। इसी सोच का ही असर है कि इस अधिनियम के पारित होने के बाद भारत के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की नजर में भारतीय विदेश नीति नाकाम नजर आने लगी है। सैद्धांतिक रूप से भारतीय वामपंथी इकोसिस्टम अमेरिका का हर पल खुला विरोध करता है, लेकिन उसे भी अमेरिकी टैरिफ कानून भारतीय हित के खिलाफ नजर आ रहा है। इन सबके बीच भारत सरकार की प्रतिक्रिया संतुलित और सधी हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपनी 140 करोड़ की आबादी की ऊर्जा सुरक्षा के लिए दृढ़ है। जाहिर है, भारत को झुकाने की सोच रखने वाले ट्रंप प्रशासन को ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं रही होगी। ऐसे में अमेरिका के अगले कदम पर निगाह रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। रूस और ईरान से अगर भारत द्वारा तेल खरीदने का बुनियादी लक्ष्य रूस– यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देना या ईरान–इजरायल युद्ध में अमेरिका और इजरायल का विरोध नहीं है। दरअसल भारत मौजूदा माहौल में अपनी भारी–भरकम जनसंख्या के लिए किफायती ऊर्जा सुरक्षा को संरक्षित कर रहा है। इसलिए भारत का न झुकना देश के विपक्षी दलों और अमेरिकी सरकार के लिए हैरतअंगेज भले ही हो, भारतीय हितों के अनुकूल नहीं है। वैसे जब से ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभाला है, अपने ऊल–जलूल फैसलों के लिए ही वे जाने गए हैं। यह पहला मौका नहीं है कि उन्होंने इस कानून के जरिए भारत को दबाने की कोशिश की है। बीते साल एक अगस्त 2025 से उन्होंने भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया था। जिससे उनके ही बाजार में भारतीय वस्तुएं और सामान महंगे होने लगे थे। तब चालाकी दिखाते हुए ट्रंप प्रशासन ने फार्मास्युटिकल्स को इस टैरिफ से अलग रखा था। इसकी वजह यह है कि भारत से अमेरिका आने वाली दवाएं सस्ती पड़ती हैं। भारतीय रत्न और आभूषणों पर टैरिफ लगाने का बहुत असर नहीं पड़ा था। क्योंकि रत्न और आभूषण स्वभाव से ही महंगे होते हैं और उन्हें खरीदने वाले लोगों के लिए इनकी महंगाई मायने नहीं रखती। ठीक वैसे ही, जैसे भारत में महंगा होने के बावजूद सोने की खरीद–बिक्री पर असर नहीं पड़ा है। भारतीय सामान जब बढ़े टैरिफ के चलते अमेरिकी बाजार में महंगे होने लगे तो अमेरिका में भी ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ सवाल उठने लगे। तब तक अमेरिकी प्रशासन को भी समझ आने लगा था कि उसने कैसा कदम उठाया है। इसका असर यह हुआ कि फरवरी 2026 में ट्रंप प्रशासन को टैरिफ में कटौती करनी पड़ी। पश्चिमी एशिया का हालिया संकट अमेरिका की ही देन है। जब से यह संकट बढ़ा है, भारत ने रूस से तेल की खरीददारी बढ़ा दी है। यह भारत की मजबूरी भी है। बीती जुलाई में भारत ने अपने कुल तेल आयात का 51.4 प्रतिशत तेल अकेले रूस से खरीदा था। रूस से तेल खरीद का भारतीय मकसद मौजूदा हालात में अपने लिए किफायती दरों पर तेल हासिल करना है। भारत का यह अधिकार है और मौजूदा हालात में अगर भारत झुकता है तो इसे भारतीय नागरिक शायद ही पसंद करेगा। और तेल की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए आसानी से होती है, इसलिए चीन भी टैरिफ युद्ध के निशाने पर होने के बावजूद तेल खरीद से पीछे नहीं हट रहा तो फिर हमें ही क्यों पीछे रहना चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति इस कानून के तहत भारत पर सौ प्रतिशत टैरिफ थोपते हैं तो भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात को बड़ा झटका लग सकता है। जानने की बात है कि भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों में टेक्सटाइल्स, रत्न और आभूषण, आटोमोबाइल और इंजीनियरिंग उत्पाद ज्यादा है। टैरिफ अगर बढ़ेगा तो अमेरिकी बाजार में इनकी कीमतें महंगी होंगी, जिससे उनकी मांग घट सकतकी है। इससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान हो सकता है। कुछ जानकारों को लगता है कि इससे रूस से जारी तेल खरीद से मिल रही अरबों रूपए की राहत खटाई में पड़ सकती है। यहां ध्यान देने की बात यह भी है कि भारत, अमेरिका से व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी रखे हुए है। अगर सौ प्रतिशत टैरिफ लागू किया जाता है तो इस प्रस्तावित व्यापार समझौते में अड़चन आ सकती है। हो सकता है कि यह बातचीत ही खटाई में पड़ जाए। बेशक अमेरिका भारत का बड़ा कारोबारी साझीदार है। लेकिन मोदी के 2024 में सत्ता में आने के बाद से अब तक करीब चालीस देशों से मुक्त व्यापार समझौता किए जा चुके हैं। भारत ने हाल ही में यूरोपीय संघ से भी ऐसा समझौता किया है। भारत का मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड आदि से मुक्त व्यापार समझौते या व्यापक आर्थिक साझेदारी का समझौता कर चुका है। भारत सरकार के ही आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने कारोबारी नेटवर्क का विस्तार करते हुए नौ बड़े मुक्त व्यापार समझौते भी किए हैं। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी ईएफटीए में आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। इसी तरह भारत ने आसियान देशों, जापान, दक्षिण कोरिया और साफ्टा के सदस्य देशों के साथ पारंपरिक कारोबारी समझौता कर चुका है। अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ थोपता है तो देश को चाहिए कि इन देशों के जरिए कारोबार को बढ़ावा दे। वैसे भी टैरिफ थोपने की दशा में भारतीय कारोबारी दूसरे देशों के जरिए अमेरिका में अपना माल भेज सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार भी ऐसी राह तलाशने की कोशिश में जुटी होगी। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था भी पहले जैसी नहीं रही, इसलिए हताश और चिंतित होने की जरूरत नहीं है, भारत को अमेरिकी बाजार में घुसने के लिए वैकल्पिक राहों की तलाश तेज करनी होगी।

मेगा हड़ताल पर आ गए सभी, वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे

अभिनय

अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जैफर्सन ने बैंक्स और फाइनेंशियल स्टैब्लिशमेंट को देश की बॉर्डर पर तैनात आर्मी से भी ज्यादा खतरनाक बताया था। बात सही भी है। सरकारों को अपने प्रशासन, डिप्लोमेसी और युद्ध तक चलाने के लिए बैंक्स और कर्ज की जरूरत पड़ती ही हैं। जैफर्सन का इशारा इस बात पर था कि बैंक सिर्फ पैसे के लेन–देन की जगह नहीं हैं, बल्कि वे पूरे देश की नब्ज और सत्ता की रीढ़ हैं। जब यह रीढ़ कुछ दिनों के लिए भी काम करना बंद कर दे, तो पूरा देश ठहर जाता है। 28 सितंबर से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (न्थ्ठन्) की देशव्यापी हड़ताल इसी हकीकत की याद दिलाती है। फर्ज कीजिए महीने का आखिरी हफ्ता है। आपकी सैलरी आनी है। ईएमआई भी जानी होगी। किसी को चेक जमा करना है। किसी को बैंक से कैश निकालना है। और इसी बीच खबर आती है कि 28, 29 और 30 सितंबर को देश भर में बैंक स्ट्राइक होने वाली है। और कैलेंडर देखिए आप 26 सितंबर को फोर्थ सैटरडे है। बैंक की छुट्टी। 27 सितंबर संडे है बैंक की छुट्टी। और 28, 29 और 30 सितंबर को स्ट्राइक का कॉल है। यानी बैंक ब्रांच से काम करने वाले लोगों के लिए दिक्कत 3 दिन की नहीं लगातार 5 दिन तक खींच सकती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि वीकेंड के साथ मिलकर यह स्ट्राइक बैंकिंग सर्विज पर 5 दिन जैसा असर डाल सकती है। तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बैंक कर्मचारी स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? आपके लिए सवाल है क्या 30 तारीख की सैलरी आएगी? यूपीआई चलेगा या नहीं चलेगा? एटीएम में पैसा मिलेगा या नहीं? चेक क्लियर होगा, ईएमआई कटेगी और आपका कोई जरूरी काम बैंक ब्रांच में अटका हुआ है तो क्या अभी निपटा लेना चाहिए? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि लाखों बैंक कर्मचारी काम–काज चोड़कर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं। सरकार इस मुद्दे पर क्या कर रही है? तमाम मामलों का एमआरआई स्कैन करेंगे। बैंक कर्मचारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस न्थ्ठन् ने इस हरताल को बुलाया है। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि बैंक्स में हफ्ते में पांच दिन के काम की व्यवस्था होनी चाहिए और हर शनिवार छुट्टी होनी चाहिए। बैंक यूनियन की मुख्य मांग है कि हफ्ते में सिर्फ पांच दिन बैंक खोलने की व्यवस्ता लागू हो। अभी बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं लेकिन बाकी दो शनिवार काम होता है। यूनियंस चाहती हैं कि सभी शनिवार को छुट्टी हो और सोमवार से शुक्रवार तक बैंक काम करें। दूसरी बड़ी मांग पीएलआई यानि परफॉर्मेंश लिंक्ड इंसेंटिव की है। इस योजना को वापस लेने की मांग है। सरकार ने फिलहाल इस योजना को स्थगित कर दिया है। नए बैंक कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू करने की मांग की गई है। इसके अलावा पेंशन अपडेट करना, पेंशन पर युनिफॉर्म, डीए पेंशनर्स के लिए मेडिकल इंशोरेंस, प्रीमियम में राहत जैसी कई और मांगे भी है, जिन पर बैंक यूनियन सरकार से एक्शन की डिमांड कर रही है। इससे पहले 11 सितंबर को भी बैंक कर्मियों ने इनी मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल की थी। सरकार से बाचीत भी हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलने की वजह से अब वो तीन दिन की हड़ताल पर जा रहा है। बैंक कर्मचारियों की जितनी भी मांगे हैं उन में से सबसे बड़ी मांग जिस पर वो टस से मस नहीं होना चाहते वो 5–कंल वर्किंग है। बैंक कर्मियों के मुताबिक उन पर काम का बहुत जादा बोझ है, जिसके चलते वो ये डिमांड पिछले 10 साल से कर रहे है। बैंक कर्मियों के मुताबिक उनसे सामान्य बैंकिंग ऑपरेशन्स के अलावा भी कई काम कराए जाते सरकार की स्कीम्स लागू करना है। म्युचल फंड्स और इंशोरेंस जैसे प्रोडक्ट को बेचना

है। ये भी काम बैंक वाले कर रहे हैं। कर्मचारियों के मुताबिक बैंकों की भर्ती प्रक्रिया बेहद ढीली है। जिसके चलते मैनपावर की कमी हमेशा बनी रहती है। इसी वजह से बैंकों में काम करने वाले लोग रोजाना 2–3 घंटे पहले ही ज्यादा काम करते है। बैंक कर्मचारियों के मताबिक एलआईसी जैसे कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स में 5–कंल वतापदह का नियम है यानी पांच दिन काम होता है तो बैंक में क्यों पांच दिन नहीं हो सकता। आप दस तरह के काम बैंक कर्मचारियों से करा रहे हैं, तो बैंक कर्मचारी कह रहे हैं कि हम भी तो इंसान हैं, हमारा भी परिवार है। क्या दिनभर सिर्फ नोट ही गिनते रहे। बैंक यूनियन्स के मुताबिक मार्च 2024 में इंडियन बैंक्स असोसियेशन आईबीए के साथ द्विपक्षीय समझोता हुआ और इसमें सहमती बनी थी। लेकिन इसे लागू करने के लिए अभी तक सरकार की आधिकारिक मंजूरी और अधिसूचना का इंतजार है। एसबीआई ने कस्टमर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। बैंक ने कहा कि जो जरूरी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें स्ट्राइक की तारीखों से पहले पूरा कर लें। कैश चाहिए तो एटीएम का इस्तेमाल करें। ।क्ड यानी ऐसी मशीन जहां से कई जगह कैश निकालने के साथ जमा भी किया जा सकता है। बैंक ने कस्टमर सर्विस पॉइंट्स इस्तेमाल करने के लिए भी कहा है और सबसे जरूरी इंटरनेट बैंकिंग, यव, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और दूसरे डिजिटल चौनल्स को प्रेफर करने को कहा है। साथ में यह भी कि स्ट्राइक के दौरान जरूरी बैंकिंग सर्विज चालू रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऐसे ही कुछ नोटिसेस बैंक ऑफ बौदा, ब्दरा बैंक, च्छठ सारे बैंक्स ने निकाले हैं। अगर आपका काम ब्रांच पर डिपेंड करता है बैंक की तो उसे आखिरी दिन के भरोसे मत छोड़िए। इस वक्त यूपीआई बिना किसी दिक्कत के चलेगा। यह स्ट्राइक बैंक कर्मचारियों की है। यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बंद करने का कोई ऐलान नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और बैंक एप्स भी नॉर्मल रहेंगे। इसी तरह ऑनलाइन एनईएफटी और आरटीजीएस भी चलते रहने चाहिए। आरबीआई के मुताबिक एनईएफटी पूरे साल 24ों घंटे उपलब्ध है। आरटीजीएस भी 24 घंटे साल के चलता रहता है। कर्मचारी यूनियनें हड़ताल के दौरान वेतन कटने के डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत में तब्दील करने की अपील कर रही हैं। बैंककर्मियों का स्पष्ट तर्क है कि दो–तीन दिन या दस दिन का वेतन कटने से कर्मचारियों के घरों पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन वे झेल लेंगे। सवाल यह है कि क्या सरकार और देश की अर्थव्यवस्था बैंकों की राष्ट्रव्यापी पूर्ण बंदी को इतने दिन बर्दाश्त कर सकती है? कर्मचारियों का मानना है कि वेतन बचाने के लिए अगर वे आज पीछे हटे, तो उनकी बारगेनिंग पावर खत्म हो जाएगी, इसलिए वे अपनी सामूहिक ताकत दिखाने के मूड में हैं।

अजय राय हत्याकांड अदालत में अभियुक्तसंजय राय से जिरह एक अक्टूबर को होगी सुनवाई

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर लालगंज (आजमगढ़) के ब्लॉक प्रमुख अजय राय हत्याकांड में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे)–6 सुरेंद्र प्रताप भादौरिया की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले के अभियुक्त संजय राय से जिरह की गई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक अक्टूबर 2026 की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह, राजेश सिंह, राकेश सिंह और संजय सिंह उपस्थित रहे। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने अपनी–अपनी पैरवी की। बताया गया कि अजय राय की वर्ष 2003 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मामले में भूपेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना, अखंड प्रताप सिंह, अनिल यादव, ध्रुव सिंह समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई लंबे समय से न्यायालय में चल रही है। अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा मामले से जुड़े तथ्यों पर जिरह की जा रही है। अगली सुनवाई एक अक्टूबर को होगी।

नशामुक्त युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव – कुलपति

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) स्थापना दिवस के अवसर पर "नशामुक्त युवादृविकसित भारत" अभियान के तहत युवाओं में शराब के दुष्प्रभावों की रोकथाम, जागरूकता एवं संरक्षण विषय पर युवा संवेदनी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम कंज्यूमर वॉयस, नई दिल्ली एवं कंज्यूमर गिल्ड, लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. आर.के. सिंह ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से युवाओं को बचाने के लिए परिवार, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों और युवाओं को मिलकर प्रयास करना होगा। नशामुक्त युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव बन सकते हैं। मुख्य वक्ता कंज्यूमर गिल्ड, लखनऊ के अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि जागरूक युवा किसी वस्तु या आदत को अपनाने से पहले उसके प्रभाव और परिणाम को समझता है। युवाओं को केवल नशे से दूर रहने की सलाह देने के बजाय खेल, योग, अध्ययन, नवाचार, सामाजिक सेवा और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना जरूरी है। सुश्री नीलजना बोस ने कहा कि दोस्तों का दबाव और सामाजिक वातावरण कई बार युवाओं के फैसलों को प्रभावित करता है। शराब को आधुनिक जीवनशैली का हिस्सा मानने जैसी सोच पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। डीएसडब्ल्यू प्रो. प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि युवा पढ़ाई, करियर, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक अपेक्षाओं के दबाव से गुजरते हैं। उन्हें उपदेश के बजाय सही जानकारी, मार्गदर्शन और सकारात्मक वातावरण देना जरूरी है। एनएसएस स्वयंसेवकों ने नशामुक्ति पर नुक्कड़ नाटक और गीत प्रस्तुत कर जागरूक किया। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. शशिकांत यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन अभिनव कीर्ति पांडेय और ओम प्रकाश मिश्र ने किया। धन्यवाद ज्ञापन सुमित सिंह ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्वयंसेवक मौजूद रहे।

जौनपुर हाईवे पर बैंक मैनेजर की कार में गोली मारकर की आत्महत्या, कार से सुसाइड नोट बरामद

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में बक्शा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग–731 पर द्वारिका होटल के सामने गुरुवार रात एक बैंक मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस ने कार से एक सुसाइड नोट बरामद किया है। मामले की जांच की जा रही है। मृतक की पहचान दुर्गेश श्रीवास्तव (35) पुत्र अवधेश श्रीवास्तव के रूप में हुई है। वह लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र स्थित कुर्सी रोड के किरन इनक्लेव के निवासी थे और जौनपुर में क्षेत्रीय बैंक मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। वर्तमान में वह जौनपुर में वन विहार के पास रह रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि दुर्गेश श्रीवास्तव अपनी टाटा सिएरा कार (यूपी32 एसए4239) से बदलापुर की ओर से जौनपुर जा रहे थे। रात करीब 8रू30 बजे बक्शा थाना क्षेत्र में हाईवे के पास उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार से उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार कार से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। घटना की सूचना परिजनों को दी गई थी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति जागरूकता अभियान आयोजित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गाँधी स्मारक पीजी महाविद्यालय, समोधपुर, शुक्रवार में को नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महाविद्यालय परिवार एवं समाज में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा युवाओं को नशामुक्त एवं स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के सेवा संकल्प अभियान के संयोजक एवं नोडल अधिकारी डॉ. लालमणि प्रजापति ने की। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और सामाजिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। युवाओं को नशे से दूर रखना केवल परिवार की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी से स्वयं नशे से दूर रहने तथा अपने आसपास के लोगों को भी नशामुक्त जीवन के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। सह–संयोजक विकास कुमार यादव ने कहा कि जागरूकता और सही मार्गदर्शन के माध्यम से नशे की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उनका स्वस्थ, शिक्षित एवं नशामुक्त रहना राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर डॉ. नीलमणि सिंह, डॉ. अविनाश वर्मा, डॉ. पंकज सिंह, डॉ. वंदना तिवारी, डॉ. जितेंद्र सिंह एवं डॉ. विष्णुकांत त्रिपाठी सहित महाविद्यालय के शिक्षकगण उपस्थित रहे और कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों पर चर्चा की गई। उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार एवं समाज में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा नशे से दूर रहने, दूसरों को भी नशामुक्त जीवन के लिए प्रेरित करने तथा स्वस्थ एवं जागरूक समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने की शपथ ली गई।

अंत्योदय से ही साकार होगा नवभारत – प्रो. संजीत गुप्ता

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद में निहित भारतीय ज्ञान परंपरा एवं नवभारत की वैचारिक आधारभूमि विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य अतिथि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के पूर्व कुलपति प्रो. संजीत गुप्ता ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान, दर्शन, विज्ञान और लोककल्याण को एक सूत्र में पिरोया गया है। यह परंपरा केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने विश्व को ज्ञान और मानव कल्याण का मार्ग दिखाया है। आज भारत अध्यात्म और दर्शन के साथ विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा की वैज्ञानिक दृष्टि का उल्लेख करते हुए कहा कि आर्यभट्ट ने सदियों पहले पृथ्वी के गोल होने और खगोलीय ज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए थे। भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की भावना के साथ उसके माध्यम से लोककल्याण करना है। अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन में अंत्योदय का भाव निहित है। तकनीक और शिक्षा तभी सार्थक हैं, जब उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। नवभारत की तकनीक गांव के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य, शिक्षा और विभिन्न सेवाएं सहजता से पहुंचाने का माध्यम बन सकती है। उन्होंने कहा कि शिक्षक और विद्यार्थी अपने ज्ञान को केवल व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित न रखें, बल्कि उसे समाजोपयोगी बनाने का प्रयास करें। शिक्षा जब संवेदना से जुड़ेगी, तभी वह समाज और राष्ट्र के वास्तविक विकास का माध्यम बनेगी। स्वागत भाषण में दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के निदेशक प्रो. मानस पांडेय ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से यह प्रश्न करना चाहिए कि वह कौन है और उसका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य की पहचान कर पूरी निष्ठा से कर्म करने पर सफलता और करियर का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके पूर्व मुख्य अतिथि और कुलपति को अभिनंदन पत्र एवं अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया गया। छात्र अभिनव कीर्ति पांडेय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी समाज का मार्गदर्शन किया और अंत्योदय को सामाजिक समरसता तथा सर्वजन हित से जोड़ने का मार्ग दिखाया। कार्यक्रम का संचालन शोधपीठ के सचिव डॉ. अनुराग मिश्रा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉ. राहुल राय ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक, शोधार्थी एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

'एसडीएम ने सेवा संकल्प अभियान के तहत छात्रों से किया संवाद, दिए करियर टिप्स'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'पाली–हरदोई)' सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को पाली कस्बे के सेठ बाबूराम भारतीय इण्टर कालेज में एक विशेष संवाद एवं करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उपजिलाधिकारी शिवानी सिंह ने छात्रध्छात्राओं से सीधा संवाद स्थापित कर उन्हें भविष्य के प्रति सजग रहने और सही करियर चयन के मूल मंत्र दिये। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उपजिलाधिकारी ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं,और सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलने से वे अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने लक्ष्य का निर्धारण केवल दूसरों की देखा देखी में न करें,बल्कि अपनी क्षमता,रूचि और मेहनत के बल पर अपना मार्ग स्वयं चुने। संवाद के दौरान एसडीएम शिवानी सिंह ने सिविल सर्विसेज,उच्च शिक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी,स्वरोजगार और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर छात्रध्छात्राओं का कुशल मार्गदर्शन किया। उन्होंने बच्चों द्वारा पूँछे गए प्रश्नों के सहजता से उत्तर दिये और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान बड़ी शालीनता से किया। एसडीएम ने कहा कि असफलता से खबराने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। कार्यक्रम के दौरान पाली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से पधारे डॉ अजीमुद्दीन एवं डॉ मीनाक्षी ने भी करियर काउंसलिंग को लेकर अपने–अपने विचार व्यक्त करते हुए बच्चों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि सफलता पाने के लिये कठिन परिश्रम के साथ–साथ शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। डॉ साहब ने मेडिकल साइंस और रिसर्च के क्षेत्र में उभरते अवसरों की जानकारी दी और छात्रों को अनुशासित रहते हुए अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करने की सीख दी। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं वरिष्ठ शिक्षकों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों को दिशा निर्देश दिए। प्रधानाचार्य डॉ वीपी द्विवेदी ने छात्रध्छात्राओं को समय प्रबंधन,नियमित अध्ययन और आत्म अनुशासन का महत्व समझाया। वहीं शिक्षक विनोद प्रताप वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ शिक्षकों ने बच्चों को विभिन्न विषयों के अनुसार करियर के उदाहरण सहित विकल्पों प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न और मूलभूत अवधारणाओं को मजबूत करने के आसान तरीके बताए। प्रधानाचार्य सहित शिक्षकों ने छात्रों को आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार के संशय या मार्गदर्शन के लिए विद्यालय परिवार सदैव उनके साथ है। वहीं एसडीएम ने विद्यार्थियों को हर संभव प्रशासनिक सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पढ़ाई, करियर या किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अथवा व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए उनके कार्यालय का दरबार बच्चों के लिए सदैव खुला रहेगा। छात्र बिना किसी झिझक के अपनी समस्याओं और मार्गदर्शन के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी(एसडीएम) से सीधे सवाल –जवाब और उचित मार्गदर्शन पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। कालेज के प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी एवं बच्चों ने सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित इस पहल की सराहना करते हुए उपजिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं काफी संख्या में छात्रध्छात्रायें मौजूद रहे।

28 से 30 सितंबर की बैंक हड़ताल में ग्राहकों को मिलेगी वैकल्पिक बैंकिंग सुविधा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (न्थ्ठन्) के आह्वान पर 28, 29 और 30 सितंबर को प्रस्तावित देशव्यापी बैंक हड़ताल के दौरान ग्राहकों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए जनपद में बैंकों ने व्यापक वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं। आम नागरिकों, व्यापारियों, किसानों और पेंशनर्स को आवश्यक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंक स्तर पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए 27 सितंबर रविवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामान्य रूप से संचालित होंगे। त्ठप् की अनुमति के अनुसार बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से संबद्ध शाखाओं और करेंसी चेस्ट को भी इस दिन संचालित रखने की व्यवस्था की गई है। ग्राहक हड़ताल से पहले अपने आवश्यक बैंकिंग कार्य निपटा सकेंगे। हड़ताल के दौरान ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में

बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जिले के सभी 1,444 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) प्वाइंट सक्रिय रहेंगे। इन केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं के तहत ग्राहक नकद जमा और निकासी, आधार आधारित बैंकिंग तथा अन्य उपलब्ध सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। बीसी प्वाइंट पर पर्याप्त नकदी उपलब्धता और सुचारु संचालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बैंकों ने ग्राहकों से शाखा जाने के बजाय आवश्यकतानुसार डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की अपील की है। ग्राहक यूपीआई, क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, एटीएम, कैश रिसाइकलर और माइक्रो–एटीएम के माध्यम से लेन–देन कर सकते हैं। बैंक अधिकारियों के अनुसार ग्राहकों को हड़ताल की पूर्व सूचना देने, एटीएम और बीसी प्वाइंट पर नकदी उपलब्ध कराने तथा महत्वपूर्ण बैंकिंग कार्यों की निगरानी की व्यवस्था की गई है। बैंक परिसरों और महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से भी समन्वय किया जा रहा है। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जौनपुर ने ग्राहकों से अपील की है कि वे शाखा आधारित आवश्यक कार्य 27 सितंबर या उससे पहले पूरा कर लें। साथ ही डिजिटल लेन–देन के दौरान ओटीपी, पिन, सीवीवी या यूपीआई पिन किसी से साझा नहीं करने और संदिग्ध लिंक व कॉल से सावधान रहने को कहा है।

गाँधी जयंती के अवसर पर पश्वक्सो एक्ट एवं बाल अधिकारों प्रति विद्यार्थियों को किया जाएगा जागरूक

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार गांधी जयंती के अवसर पर पॉक्सों एक्ट, 2012 के प्रावधानों, कानूनी नतीजों तथा महिला एवं बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तक चलाया जा रहा है। प्रथम चरण के तहत जनपद के विभिन्न विद्यालयों में न्यायिक अधिकारियों एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ताओं द्वारा विद्यार्थियों को कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। अभियान के तहत न्यायिक अधिकारी विद्यालयों में प्रातः कालीन सभा (मॉर्निंग असेंबली) के दौरान विद्यार्थियों को पॉक्सों एक्ट, 2012 के प्रमुख प्रावधानों, बच्चों के अधिकारों, महिला एवं बाल संरक्षण से संबंधित कानूनी व्यवस्थाओं तथा कानून का उल्लंघन करने पर होने वाले कानूनी परिणामों के बारे में एवं हेल्पलाइन नं0 के बारे में भी जागरूक करेंगे। विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण, बाल संरक्षण एवं किसी भी प्रकार के शोषण की स्थिति में उपलब्ध कानूनी सहायता के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। नर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 26 सितम्बर को प्रातः 09:00 बजे टी0डी0 इण्टर कालेज, राजा श्री कृष्णदत्त इण्टर कालेज, 28 सितम्बर को जनक कुमारी इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, 29 सितम्बर को मो0 हसन इण्टर कालेज, बी0आर0पी0 इण्टर कालेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान के तहत समस्त पैनल अधिवक्ता, पराविधिक स्वयं सेवकगण द्वारा अपने–अपने क्षेत्रों के विद्यालयों में पॉक्सों एक्ट, 2012 के प्रमुख प्रावधानों, बच्चों के अधिकारों, महिला एवं बाल संरक्षण से संबंधित कानूनी व्यवस्थाओं तथा कानून का उल्लंघन करने पर होने वाले कानूनी परिणामों के बारे में एवं हेल्पलाइन नं0 के बारे में जानकारी प्रदान करायेगें। अभियान के दौरान न्यायिक अधिकारियों के साथ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता भी विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। श्री प्रशान्त कुमार सिंह, प्रभारी सचिवध्अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशध्एफ0टी0सी0 द्वितीय, जौनपुर ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक और सुरक्षित बनाना तथा आवश्यकता पड़ने पर विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है।

फार्मासिस्ट स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग: डॉ. नृपेंद्र सिंह

जौनपुर । वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के फार्मेसी विभाग में शुक्रवार को विश्व फार्मासिस्ट दिवस उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। इस वर्ष की थीम इंपावरिंग फार्मासिस्ट फार ए हेल्थियर फ्यूचर अर्थात "स्वस्थ भविष्य के लिए फार्मासिस्टों को सशक्त बनाना" को केंद्र में रखते हुए विभाग में विभिन्न रचनात्मक एवं जागरू कतापरक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ विभागाध्यक्ष डॉ. नृपेन्द्र सिंह एवं प्रो. नरेन्द्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रस्तुति तथा निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें फार्मेसी विभाग के छात्र–छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। विभागाध्यक्ष डॉ. नृपेन्द्र सिंह ने कहा कि फार्मासिस्ट स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग हैं। उन्होंने दवाओं के तर्कसंगत एवं उचित उपयोग पर विशेष जोर देते हुए कहा कि मरीजों को दवाओं की सही मात्रा, सही समय और सही तरीके से सेवन के संबंध में उचित परामर्श देना फार्मासिस्ट की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। प्रो. नरेन्द्र सिंह ने कहा कि फार्मेसी के छात्रों को अपने ज्ञान और व्यावसायिक कौशल का उपयोग समाज के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। उन्होंने एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बढ़ते खतरे पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक एवं गलत उपयोग भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बन सकता है। डॉ. विजय बहादुर मौर्य ने कहा कि बदलती स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप फार्मासिस्टों का ज्ञान, कौशल और व्यावसायिक क्षमता के स्तर पर सशक्त होना आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर सीखने तथा अपने ज्ञान एवं कौशल में निरंतर अभिवृद्धि करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती पूजा और धन्यवाद ज्ञापन विभागाध्यक्ष डॉ. नृपेन्द्र सिंह ने किया। इस अवसर पर डॉ. सुरेंद्र कुमार सिंह, डॉ. झांसी मिश्रा, डॉ. सुरेंद्र कुमार गौतम, अभिषेक कुमार यादव, शक्ति जायसवाल , हेमन्त दूबे एवं प्रशांत यादव सहित बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे।

महापौर ने विस्थापित परिवारों से मुलाकात कर समस्याओं के शीघ्र निदान का दिया भरोसा

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।नाका क्षेत्र में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण के चलते विस्थापित हुए दुकानदारों को नगर निगम वेंडिंग जोन बनाकर दुकानें उपलब्ध कराएगा।महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने शुक्रवार को विस्थापित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानीं और यथासंभव मदद का भरोसा दिया।इस दौरान नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार भी मौजूद रहे।सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में महापौर ने कहा कि विस्थापित दुकानदारों के पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन से लगातार बातचीत चल रही है।जैसे ही जिला प्रशासन नगर निगम को नजूल की जमीन उपलब्ध कराएगा।वहां वेंडिंग जोन विकसित कर प्राथमिकता के आधार पर विस्थापित परिवारों को दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी।उन्होंने कहा कि अक्षय नवमी के अवसर पर होने वाली 14 कोसी परिक्रमा से पूर्व सड़क निर्माण कार्य पूरा करना आवश्यक था।विकास कार्य के दौरान जिन लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, उनके साथ योगी सरकार न्याय करेगी। फिलहाल बारिश और धूप से बचाव के लिए विस्थापित दुकानदारों को अस्थायी शेड उपलब्ध कराने का निर्णय नगर निगम ने लिया है। साथ ही वहां मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था भी की जा रही है।

महापौर ने कहा कि दुकानदारों और जिला प्रशासन से निरंतर संवाद किया जा रहा है।सभी को सरकार की व्यवस्था और न्याय पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जिस गति से विकास कार्य हो रहे हैं, वह अभूतपूर्व हैं। विकास के इस दौर में कुछ स्थानों पर स्थानीय लोगों को असुविधा जरूर हुई है, लेकिन आने वाले समय में इसका लाभ कहीं अधिक व्यापक होगा।

महापौर ने बिना नाम लिए विपक्षी दलों पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सवाल उठाने वाले और पूर्व में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण में बाधा पहुंचाने वाले लोगों को अब सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है।एक सवाल के जवाब में महापौर ने कहा कि अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई अब जोनल अधिकारी की मौजूदगी के बिना नहीं की जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।नगर आयुक्त जल्द ही प्रवर्तन दल को कैमरे उपलब्ध कराएंगे, ताकि कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड हो सके और किसी अप्रिय स्थिति में तथ्यात्मक आधार पर उचित कार्रवाई की जा सके।नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि महापौर के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया है। जल्द ही अस्थायी शेड बनाकर विस्थापित दुकानदारों को उपलब्ध कराया जाएगा। मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था भी तत्काल की जा रही है। वेंडिंग जोन तैयार होते ही प्राथमिकता के आधार पर विस्थापित दुकानदारों को दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी।इससे पूर्व महापौर ने मुरारी यादव समेत विस्थापित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त डॉ नागेंद्र नाथ, भाजपा मंडल अध्यक्ष हेमंत जायसवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष आलोक द्विवेदी, जगदीश चतुर्वेदी, सुनील चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे।

प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिलाधिकारी को सौंपा मांगपत्र

ब्यूरो चीफ . आलोक कुमार श्रीवास्तव

सुलतानपुर। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को बीएलओ सहित अन्य गैर–शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष दिलीप पाण्डेय के नेतृत्व में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह के कार्यालय पहुंचा और मांगपत्र सौंपा। जनपदीय प्रवक्ता निजाम खान ने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में परिषदीय शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी लगाए जाने से शिक्षण कार्य प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि शिक्षक पहले से ही विद्यालयी शिक्षण, प्रशासनिक एवं विभागीय दायित्वों के साथ 69000 भर्ती के बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स में भी व्यस्त हैं। ऐसे में अतिरिक्त गैर–शैक्षणिक दायित्वों से विद्यालयों में पठन–पाठन प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 27 के तहत शिक्षकों को गैर–शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने का प्रावधान है तथा निर्धारित अपवादों में ही शिक्षकों की सेवाएं ली जा सकती हैं। संघ ने शासनादेशों एवं न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त रखने की मांग की। संघ ने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि शिक्षकों को विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए उपलब्ध रखा जाए, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। प्रतिनिधिमंडल में शिक्षक संघ के पदाधिकारी एवं शिक्षक मौजूद रहे।संरक्षक अखिलेश उपाध्याय,वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र नारायण मिश्रा, संयुक्त मंत्री प्रशांत पाण्डेय,भदैयाअध्यक्ष अंजनी शर्मा मंत्री दुबेपुर हेमंत यादव, युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र राव,संतोष पाण्डेय,राजमणि यादव, विमलेश,दिनेश बरनवाल, कीर्ति वर्णवाल, हरे कृष्णा, सुनील कुमार ,महेंद्र कुमार सरोज ,बृजेश कुमार, प्रवीण कुमार, उमेश कुमार, मिथिलेश कुमार ,अनीता देवी, अखिलेश कुमार, अजय कुमार, अशरफ मोईद ,मोहित ओमकार ,राजभवन, आनंद सागर संजय कुमार ,विपिन कुमार तिवारी, अतुल कुमार यादव, सुजीत कुमार यादव इत्यादि रहे ।

14 कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण प्रभावितों को मिला मुआवजा

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।14 कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण की जद में आए प्रभावितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।कलेक्ट्रेट सभागार में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व जिला प्रशासन की मौजूदगी में प्रभावितों के साथ बैठक हुई।प्रशासन के मुताबिक भवन, टिनशेड और दुकानों के आकलन के आधार पर मुआवजा दिया गया।जिसमे मुरारी सिंह यादव 63.89 लाख,घनश्याम यादव 68.29 लाख, रविन्द्र कुमार (भवन) 8.07 लाख, आशा देवी (भवन) 8.07 लाख, अमित सिंह (भवन) 9.83 लाख, दीप चन्द्र गुप्ताश्शक्ति गुप्ता (भवन) 16.99 लाख, नीलाम्बर 5.22 लाख, प्रीती 19. 87 लाख और श्याम सुंदर यादव को 93.89 लाख रुपये मिला।वहीं दुकानदारों में मोहित यादव को 1.81 लाख, पूनम गुप्ता 1.99 लाख, राजेन्द्र यादव 2.32 लाख, हरिराम यादव 2.05 लाख, रोहित यादव 1. 36 लाख, घनश्यामश्मुरारी 2.32 लाख, रविन्द्र कुमार 1.04 लाख, अमित सिंह 1.42 लाख, दीप चन्द्र गुप्ताश्शक्ति गुप्ता 2.19 लाख, अमर यादव 2.01 लाख और आनंद यादव को 1.78 लाख रुपये दिए गए। प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास के लिए नगर निगम की ओर से वेंडिंग जोन बनाकर दुकानें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।इससे प्रभावित दुकानदारों को दोबारा कारोबार शुरू करने में मदद मिलेगी।

बारिश के बीच नम आंखों से दी गणपति बप्पा को विदाई गाजे–बाजे के साथ निकली शोभायात्रा

अयोध्या।राम नगरी में गणेश उत्सव के समापन पर शुक्रवार को गणपति बप्पा को नम आंखों से विदाई दी गई।रुक–रुककर हो रही बारिश के बीच शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित गणेश प्रतिमाओं की भव्य शोभायात्राएं निकाली गईं।सुबह से ही गाजे–बाजे और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के बीच श्रद्धालु प्रतिमाओं को लेकर गुप्तार घाट स्थित निर्मली कुंड पहुंचे।जहां विधि–विधान के साथ विसर्जन किया गया।शोभायात्रा में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।श्रद्धालु रास्ते भर एक–दूसरे को गुलाल लगाते और गणपति बप्पा के जयकारे लगाते नजर आए।बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ और पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा।गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से जगह–जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए।शोभायात्रा के मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ भीड़ और यातायात व्यवस्था पर नजर रखी गई।निर्मली कुंड और आसपास के क्षेत्र में देर रात तक चलने वाले विसर्जन को देखते हुए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था भी की गई।

कोतवाली अयोध्या पुलिस ने 21.5 किलो गांजे के साथ पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार

अयोध्या।कोतवाली अयोध्या पुलिस ने 21 किलो 500 ग्राम अवैध गांजे के साथ पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया।पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त आर भी बरामद किया। संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अयोध्या पंकज सिंह ने बताया कि 25 सितंबर को करीब 3रू36 बजे बूथ नंबर–4 ओवरब्रिज सर्विस लेन के पास कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपियों को पकड़ा गया।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मदन लुबरू निवासी उड़ीसा, जितेंद्र राजभर व पवन कुमार राजभर निवासी आजमगढ़ तथा वीरूदी अनुशा और किल्लो सौजन्या निवासी आंध्र प्रदेश के रूप में हुई।गिरफ्तार करने वाली टीम में उनके अलावा उप निरीक्षक प्रवीण मिश्र,नीरज गुप्ता, अजय कुमार और उदयवीर सिंह, हेड कांस्टेबल सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी, कांस्टेबल राहुल कुमार, रवीन्द्र कुमार यादव और राधेश्याम सत्यम राय,सिद्धार्थ यादव और लवकुश कुमार, महिला आरक्षी रिन्की तथा दिव्याशी शामिल रहीं।

भदोही में अनियंत्रित होकर घर में घुसा ट्रेलर

भदोही, (संवाददाता)। भदोही जिले में औराई–मिर्जापुर मार्ग पर पुरुषोत्तमपुर तिराहे के पास बुधवार को तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक कच्चे मकान में जा घुसा। हादसे में घर में सो रही 70 वर्षीय वृद्धा कुंती देवी और ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि ट्रेलर रेलवे के बड़े–बड़े लोहे के गार्डर लेकर मिर्जापुर की ओर जा रहा था। पुरुषोत्तमपुर तिराहे के अंधे मोड़ पर चालक ने ट्रेलर को दाहिनी ओर मोड़ने का प्रयास किया। तेज रफ्तार होने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रेलर दूसरी लेन में पहुंचकर सड़क किनारे गरीब विधवा कुंती देवी के मकान में जा घुसा। टक्कर इतनी तेज थी कि कच्चा मकान क्षतिग्रस्त होकर गिर गया और ट्रेलर भी पलट गया। भोर में तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में फंसी वृद्धा तथा घायल चालक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

सेवा संकल्प अभियान झाड़ू लगाकर की सफाई

भदोही, (संवाददाता)। सेवा संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को पुलिस लाइन और विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में विशेष श्रमदान अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य लोगों ने सहभागिता करते हुए स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने का संकल्प लिया। लोगों ने झाड़ू लगाकर गंदगी की सफाई की। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, जिलाधिकारी शैलेष कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी एवं मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी अभियान में शामिल हुए।

नाका के विस्थापित दुकानदारों को मिलेंगी दुकानें, नगर निगम बनाएगा वेंडिंग जोन

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण से विस्थापित हुए नाका क्षेत्र के दुकानदारों के पुनर्वास के लिए नगर निगम वेंडिंग जोन विकसित कर दुकानें उपलब्ध कराएगा।शुक्रवार को महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने विस्थापित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और शीघ्र समाधान का भरोसा दिया। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में महापौर ने बताया कि विस्थापित दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर जिला प्रशासन से लगातार वार्ता चल रही है।नजूल भूमि उपलब्ध होते ही वहां वेंडिंग जोन विकसित कर प्राथमिकता के आधार पर विस्थापित दुकानदारों को दुकानें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल बारिश और धूप से बचाव के लिए अस्थायी शेड तथा मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था नगर निगम कर रहा है। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने भी स्थलीय निरीक्षण के बाद जल्द शेड लगाने और मोबाइल टॉयलेट उपलब्ध कराने की बात कही।महापौर ने कहा कि विकास कार्यों के दौरान विस्थापित हुए लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा।वहीं, अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को लेकर उन्होंने निर्देश दिया कि अब जोनल अधिकारी की मौजूदगी के बिना कार्रवाई नहीं होगी। प्रवर्तन दल के कैमरे उपलब्ध कराकर कार्रवाई की रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी।इससे पूर्व महापौर ने मुरारी यादव समेत विस्थापित परिवारों से मुलाकात की।इस दौरान अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ, भाजपा मंडल अध्यक्ष हेमंत जायसवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष आलोक द्विवेदी, जगदीश चतुर्वेदी और सुनील चतुर्वेदी समेत अन्य मौजूद रहे।

बड़हलगंज में किन्नरों के दो गुटों में छिड़ी वर्चस्व की जंग, कोतवाली बनी अखाड़ा, 400 किन्नरों का जमावड़ा

गोरखपुर, (संवाददाता)। बड़हलगंज क्षेत्र में यजमानों और बधाई वसूली के वर्चस्व को लेकर किन्नर समाज के दो गुटों के बीच जारी विवाद बुधवार को बड़हलगंज कोतवाली परिसर में सार्वजनिक अखाड़े में तब्दील हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों से दर्जनों बोलेरो व कारों के काफिले से करीब 400 किन्नर कोतवाली में उतर पड़े। परिसर में ही आमने–सामने आए दोनों गुटों ने ताली बजाकर अपनी गुप्त भाषा में एक–दूसरे को अपशब्द कहना शुरू कर दिया, जिससे भारी पुलिस बल के सामने ही हिंसक संघर्ष और मारपीट जैसी गंभीर स्थिति बन गई। सुबह 10 बजे से ही कोतवाली परिसर में किन्नरों का जुटना शुरू हो गया था। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों पक्ष आर–पार के मूड में दिखे और कोतवाली परिसर में हंगामे के चलते हड़कंप मच गया। स्थिति की गंभीरता और संभावित बड़े बवाल को भांपते हुए कोतवाल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने तुरंत अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाला और कड़ा रुख अपनाते हुए पहले उग्र हो रहे किन्नरों को तितर–बितर कर माहौल संभाला। मामले को शांत कराने के बाद पुलिस ने दोनों गुटों के मुखियाओं को चेंबर में

तलब किया। बड़हलगंज पक्ष से लल्लन व बिजली किन्नर तथा देवरिया पक्ष से सरोजा व कोमल किन्नर को आमने–सामने बैठाकर वार्ता शुरू की गई। बड़हलगंज के किन्नर लल्लन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाल ने दोनों पक्षों की बात सुनी और बीच का रास्ता निकालते हुए सीमा तय की। समझौते के तहत देवरिया क्षेत्र के किन्नरों को बड़हलगंज की सीमा स्थित डेडरवा तक के यजमानों को डील करने का अधिकार दिया गया, जिसके बाद जाकर दोनों पक्ष शांत हुए। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार, बधाई और यजमानी वसूली के इलाकों को लेकर दोनों गुटों में कई दिनों से खींचातान चल रही थी। पुलिस के इस त्वरित हस्तक्षेप और लिखित–मौखिक समझौते के बाद फिलहाल कई दिनों से जारी इस हाई–वोल्टेज ड्रामे पर विराम लग गया है।

तुर्कमानपुर में बिजली चोरी की जांच के दौरान धक्का-मुक्की पर शासन सख्त

गोरखपुर, (संवाददाता)। नार्मल उपकेंद्र से जुड़े तुर्कमानपुर–पहाड़पुर क्षेत्र में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम के साथ हुई धक्का–मुक्की को शासन ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हाई लॉस फीडरों की हर हाल में जांच कराई जाए। बिजली चोरी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए अभियान तेज करने को कहा गया है। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी बिजली निगम के अधिकारियों से शहर में बिजली के हाल के बारे में जानकारी ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने लाइन लॉस को लेकर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बिजली निगम के अभियंता तुर्कमानपुर में एक–एक कनेक्शन की जांच की योजना बनाने में जुट गए हैं। जांच के दौरान स्थिति को देखते हुए पीएसी की मदद लेने पर भी विचार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने के लिए अब व्यापक स्तर पर जांच की जाएगी। अभियंताओं के अनुसार मंगलवार को बिजली चोरी मिलने के बाद अचानक बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए थे। भीड़ ने अभियंताओं के साथ ही विजिलेंस टीम के दरोगा और सिपाहियों से धक्का–मुक्की की। इससे मौके पर काफी देर तक तनाव की स्थिति बनी रही। टीम के सदस्यों के साथ अभद्रता और विरोध के दौरान कुछ लोग अन्य लोगों को जांच टीम को बंधक बनाने के लिए भी उकसा रहे थे। अधीक्षण अभियंता शहरी रणजीत चौधरी ने बताया कि कई वर्षों बाद जांच टीम के साथ इस तरह की स्थिति सामने आई है। अब शासन के निर्देश के बाद क्षेत्र में बिजली चोरी की जांच को प्राथमिकता के आधार पर कराने की तैयारी की जा रही है।

ब्रह्मांड के रहस्यों से रूबरू हुए विश्वविद्यालय के विद्यार्थी

गोरखपुर, (संवाददाता)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में बुधवार को आचार्य देवेंद्र शर्मा स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें प्रख्यात भौतिकविद्, कोलकाता में कण विज्ञान के आचार्य प्रो. जयति केशरी नायक ने विद्यार्थियों और शोधार्थियों को आधुनिक भौतिकी तथा खगोल विज्ञान के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। व्याख्यान में प्रो. नायक ने ब्रह्मांड के निर्माण, अंतरिक्ष में होने वाली जटिल प्रक्रियाओं और कण विज्ञान से जुड़े नवीनतम शोध को सरल एवं रोचक तरीके से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से ब्रह्मांड के निर्माण से जुड़ी परिस्थितियों को प्रयोगशाला में समझने और पुनरू उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है।

युवक के साथ देख प्रेमी ने महिला पर किया हमला

गोरखपुर, (संवाददाता)। गुलरिहा थाना क्षेत्र में मंगलवार की मध्यरात्रि पुराने प्रेम संबंध को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि महिला को दूसरे युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद उसके पुराने प्रेमी ने हंसिया से हमला कर दिया। हमले में महिला के हाथ में गंभीर चोट आई। महिला की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि गांव के एक किसान युवक का महिला से पिछले कई वर्षों से प्रेम संबंध था। मंगलवार की रात युवक महिला के घर पहुंचा। आरोप है कि घर के बरामदे में बच्चे सो रहे थे। युवक कमरे में पहुंचा तो महिला को वहां पहले से मौजूद दूसरे युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा।

क्षेत्र के बंटवारे के लिए किन्नरों के दो गुट आमने-सामने, हंगामा

गोरखपुर, (संवाददाता)। यजमानी और बधाई वसूली के क्षेत्र को लेकर किन्नर समाज के दो गुटों के बीच चल रहा विवाद बुधवार को बड़हलगंज कोतवाली पहुंच गया। दोनों पक्षों के करीब 400 किन्नर गाड़ियों के काफिले के साथ कोतवाली पहुंचे। आमने–सामने आने के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी और हंगामा होने लगा। स्थिति बिगड़ने की आशंका पर पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग किया। सुबह करीब 10 बजे से ही दोनों पक्षों के लोगों का कोतवाली पहुंचना शुरू हो गया था। संख्या बढ़ने के साथ परिसर में तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने अतिरिक्त बल की मदद से दोनों पक्षों को अलग–अलग किया और मामला शांत कराया। इसके बाद दोनों गुटों के प्रतिनिधियों को कोतवाल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने अपने कक्ष में बुलाकर बातचीत की। बड़हलगंज पक्ष से लल्लन और बिजली किन्नर जबकि देवरिया पक्ष से सरोज और कोमल किन्नर को वार्ता में शामिल किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद क्षेत्र को लेकर अस्थायी सहमति बनाई। बताया गया कि समझौते के तहत देवरिया क्षेत्र के किन्नरों को बड़हलगंज सीमा में डेरवा तक यजमानों से बधाई लेने की अनुमति दी गई है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद शांत हुआ और वे लौट गए। स्थानीय लोगों के अनुसार, यजमानी के क्षेत्र को लेकर दोनों गुटों के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। कोतवाल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच क्षेत्र को लेकर विवाद था। फिलहाल देवरिया पक्ष को डेरवा तक की सीमा दी गई है। सरोज के गुरु तय होने के बाद क्षेत्र का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा।

रिवीजन में तीन आदेश रिकॉर्ड पर लेने की अर्जी, अनुष्का ने दी अर्जी, सुनवाई में बाधा का आरोप

वाराणसी, (संवाददाता)। ज्ञानवापी से जुड़े मूल वाद में वाद मित्र की नियुक्ति से संबंधित रिवीजन अब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, एंटी करप्शन सुधाकर राय की अदालत में स्थानांतरित हो गई है। अनुष्का तिवारी ने सीमित कानूनी प्रस्तुति को अभिलेख पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। रिवीजन की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। आवेदन के साथ 11 अप्रैल 2025, सात जुलाई 2025 और 16 दिसंबर 2025 को संबंधित स्थानांतरण वादों में पारित आदेशों की प्रतियां दाखिल की गई हैं। आवेदिका की ओर से कहा गया है कि ये कार्यवाहियां अलग–अलग मूल वादों से जुड़ी हैं, लेकिन सभी का संबंध स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर से है। प्रार्थना पत्र में 12 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश का भी उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि उक्त आदेश का विभिन्न न्यायिक कार्यवाहियों में संदर्भ दिया गया है। ऐसे में संबंधित स्थानांतरण आदेशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अभिलेख पर लिया जाना जरूरी है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन), एफटीसी अभिषिक्त यादव की अदालत में लंबित ज्ञानवापी मूल वाद संख्या में अनुष्का तिवारी ने वादी संख्या–5 एवं नेक्स्ट फ्रेंड विजय शंकर रस्तोगी के आचरण को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है।

अस्पताल में गरम पट्टी 12 दिन से खत्म, निजी दुकानों से 300 रुपये में खरीद रहे लोग

भदोही, (संवाददाता)। महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में 12 दिन से खत्म हुई गरम पट्टी (क्रेप बैंडेज व गॉज) अब तक नहीं आ सकी है। विभाग की ओर से स्टॉक खत्म होने से तीन दिन पहले ही शासन को गरम पट्टी की डिमांड के साथ पत्र लिखा गया था, लेकिन अब तक पट्टी नहीं आ सकी है। अस्पताल परिसर में स्थित जन औषधि केंद्र पर भी मरीजों को पट्टी नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से उन्हें निजी मेडिकल स्टोर से 300 रुपये खर्च कर पट्टी खरीदनी पड़ रही है। मौसम में बदलाव होने से इन दिनों भदोही एमबीएस अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है। रोजाना करीब 900 से 1000 की ओपीडी होती है। इसमें आर्थो विभाग की ओपीडी 70 से बढ़कर 100 पहुंच गई है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी ओपीडी में पहुंचते हैं। अस्पताल में हड्डी के डॉ. चन्द्रबली व डॉ. विनय मिश्रा की तैनाती है। हर दिन ओपीडी में पहुंचने वाले मरीजों में 20 मरीजों को गरम पट्टी की जरूरत पड़ती है, लेकिन पट्टी न होने के कारण उन्हें

बाहर के मेडिकल स्टोर का रुख करना पड़ रहा है। एक पट्टी खरीदने पर 300 रुपये खर्च होते हैं। जन औषधि केंद्र पर यह पट्टी 20 रुपये में मिलती है, लेकिन वहां से भी मरीज को बाहर भेज दिया जा रहा है। स्टोर में स्टॉक खत्म होने के कारण डॉक्टर बाहर से पट्टी लिखने को मजबूर हैं। मर्यादपट्टी के मरीज मुस्तफा अंसारी ने बताया कि उनके पैर में चोट लगी थी। गरम पट्टी बाहर से लेना पड़ा। भदोही नगर के पवन कुमार ने बताया कि अस्पताल में निरुशुल्क उपचार का दावा किया जाता है, लेकिन यहां हर चीज बाहर से लेनी पड़ती है। यहां तक कि 11.30 बजे के बाद लैब में जांच नहीं होती है। मरीज को बाहर भेजा जाता है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार-पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।